सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

प्रधान संपादकः रतन प्रकाश सिंह

www.swarajindianews.com swarajindianews swarajindianews

दैनिक सांध्यकालीन

स्वराज इंडिया

राहुल गांधी के खिलाफ केस की सुनवाई अब लखनऊ की कोर्ट में होगी, मिली मंजूरी

» Pg12

कानपुर, बुधवार, 17 दिसंबर, 2025
वर्षः 02, अंकः 335, पृष्ठः 8+4, मूल्यः ₹ 2/-

इनसाइड खनन माफियाओं पर कार्रवाई से कांप रहे जिमेदारों... » Pg08

महिला सम्मान पर राजनीति की दोहरी पाठशाला

हिजाब बनाम घूंघट: दो वीडियो पर मचा बवाल

नीतीश-संजय निषाद के खिलाफ सुमैया राणा ने कैसरबाग कोतवाली में दी शिकायत

नीतीश के बचाव में उतरे संजय निषाद, कहा- नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कही और छूते तब क्या हो जाता

सुमैया राणा, सपा नेत्री

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जमकर बिहार सरकार और सीएम नीतीश पर हमला बोल रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग भी उठा रही हैं। यह मामला सामने आने के बाद से नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के सीएम ने सार्वजनिक रूप से किसी महिला के चेहरे से पर्दा हटाया हो। नीतीश से पहले कांग्रेस के ही एक सीएम एक कार्यक्रम के दौरान सबके समाने महिला का घूंघट हटा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की नेत्री ने लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में बिहार सीएम के साथ यूपी की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ धारा 354 के अंतर्गत कार्रवाई का आग्रह करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है।

दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौप रहे थे। इसी दौरान एक मुस्लिम युवती नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची थी, उस युवती ने हिजाब पहन रखा था। सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र देने के बाद उसका हिजाब हटाने की कोशिश की। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो पर यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी है। संजय निषाद ने तंज कसते हुए कहा कि वो भी एक आदमी है। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कही और छूते तब क्या हो जाता।

वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार के वीडियो पर सपा नेता सुमैया राणा ने कहा कि जब से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का वीडियो देखा है, तब से अजीब सी सोच दिमाग में आ रही थी कि किस तरीके की सोच रखते हैं। एक महिला जो पर्दा करके आई थी, इसका मतलब वो पहले से पर्दा करती है। उन्होंने महिला का हिजाब खींचा और उसके बाद हंसने लगे। इसका क्या मतलब निकलता है। इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। एक समाज को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की नेता व प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में शिकायत की है। उन्होंने कहा अगर सख्त कार्रवाई और मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो हम इस मामले में घेराव करेंगे।

राधिका खेड़ा, भाजपा नेत्री

पूर्व सीएम अशोक गहलोत का वीडियो वायरल

सीएम नीतीश ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 1,200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इसी दौरान एक हिजाब पहने एक महिला डॉक्टर भी नीतीश से पत्र लेने पहुंची। डॉक्टर को पत्र देने के बाद नीतीश ने उनके चेहरे से हिजाब नीचे खींच दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और बिहार सीएम की जमकर आलोचना होने लगी। विपक्ष इसे महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा बताकर नीतीश के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा भी करने लगा। लेकिन अब इसी बीच कांग्रेस सरकार में राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत का भी एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

पूर्व सीएम गहलोत ने महिला का घूंघट हटाया

इस वीडियो में गहलोत एक कार्यक्रम के दौरान एक हिंदू महिला से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गहलोत महिला से बात करते हुए खुद अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देते हैं। महिला का घूंघट हटाने के साथ ही गहलोत उसे यह भी कहते हैं कि घूंघट प्रथा अब खत्म हो चुकी है। यह वीडियो कुछ साल पुराने एक कार्यक्रम का है लेकिन नीतीश के हिजाब हटाने वाली घटना के बाद यह अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

बीजेपी ने गहलोत का वीडियो शेयर कर पूछा सवाल

गहलोत का यह वायरल वीडियो यहीं खत्म नहीं होता बल्कि इसमें आगे गहलोत एक मुस्लिम महिला के साथ दिखाई देते हैं। वीडियो में मुस्लिम महिला बुर्का पहने होती है लेकिन गहलोत उसका बुर्का नहीं हटाते। गहलोत उससे बात करके आगे बढ़ जाते हैं। इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सदस्य राधिका खेड़ा ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते किया है। खेड़ा ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से सवाल करते हुए लिखा, आपका और राहुल गांधी की इस वीडियो पर प्रतिक्रिया कहां है। क्या आपके आलाकमान ने इसके लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगी थी। क्या हिंदू महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है।

कोर्ट जाते समय पत्नी से पति ने की सरेआम मारपीट, पीड़िता चुटहिल

112 पर कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस, आरोपी पति गिरफ्तार

»प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में बहन के साथ कोर्ट जा रही एक महिला पर उसके पति ने साथियों के साथ सरेआम मारपीट की। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने मौके से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

मिर्जापुर निवासी महेश्वरी देवी ने बताया कि उनकी बेटी तान्या की शादी एक वर्ष पूर्व इंद्रा नगर निवासी शिवम कटियार से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर तान्या के साथ मारपीट करने लगा। महेश्वरी देवी के अनुसार, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद आरोपी ने तान्या को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने बताया कि पति के खिलाफ दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। इसी सिलसिले में तान्या अपनी छोटी बहन के साथ कोर्ट जा रही थी। आरोप है कि आरोपी पति शिवम कटियार अपने कुछ साथियों के साथ कल्याणपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही उसने तान्या और उसकी बहन को देखा, वह उन पर टूट पड़ा और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी ने मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए जान से मारने की भी धमकी दी। बचाकर 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और इसके बाद चौकी पहुंचकर लिखित शिकायत दी। थाना प्रभारी राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि आरोपी पति शिवम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

कानपुर मेट्रो: नौबस्ता की ओर काम की तेज रफ्तार, एस्केलेटर-लिफ्ट तैयार

» बारादेवी से नौबस्ता तक 5 स्टेशनों पर 15 एस्केलेटर और 16 लिफ्ट इंस्टॉल

» ऊर्जा संरक्षण में कानपुर मेट्रो को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया

»प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-1 के तहत तीसरे चरण में कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा के विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस चरण में बारादेवी से नौबस्ता तक बनाए जा रहे पांच एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुल 15 एस्केलेटर का इंस्टालेशन पूरा कर लिया गया है।

प्रत्येक स्टेशन पर प्रवेश द्वार से कॉनकोर्स और कॉनकोर्स से प्लेटफॉर्म तक आवागमन के लिए तीन-तीन एस्केलेटर लगाए गए हैं।इसके साथ ही इन पांचों स्टेशनों पर प्रस्तावित 20 में से 16 लिफ्टों का काम भी पूरा हो चुका है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और महिलाओं को बड़ी

सहूलियत मिलेगी।

वहीं झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशनों पर भी सिस्टम इंस्टालेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इन दोनों स्टेशनों पर कुल आठ में से सात एस्केलेटर लगाए जा चुके हैं और शेष कार्य अंतिम चरण में है।मंगलवार को यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 के निर्माणाधीन स्टेशनों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाओं के विस्तार के लिए मेट्रो की पूरी टीम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समयबद्ध लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिविल निर्माण और सिस्टम इंस्टालेशन के कार्य समानांतर रूप से किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान निदेशक रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम नवीन कुमार, निदेशक वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीपी सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

कानपुर मेट्रो को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि भी मिली है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कानपुर मेट्रो को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहरलाल ने यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार को 'सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' प्रदान किया, जिससे कानपुर मेट्रो की ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता मिली है।

केआईटी छात्रा का आरोप- विभागाध्यक्ष भेजते आपत्तिजनक संदेश

कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रहे ऑटोनॉमस विवाद के बीच एक नया मामला सामने आया है। संस्थान की एक छात्रा ने एक विभागाध्यक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि विभागाध्यक्ष निजी और आपत्तिजनक संदेश भेजते थे, व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल पूछते थे और फिर कार्यालय में अकेले बुलाते थे। छात्रा का दावा है कि ऐसी कई और छात्राएं भी हैं जिन्हें इसी तरह के संदेश भेजे गए। प्रथम वर्ष की छात्राओं को निशाना बनाया जाता था।

हालांकि छात्रा की ओर से मामले की कही कोई शिकायत नहीं की गई है। किसी अन्य छात्रा ने इसकी पुष्टि भी नहीं की। वहीं निदेशक प्रो. ब्रजेश वार्ष्णेय का कहना है कि यह आरोप गलत हैं। छात्रा की ओर से पहले कभी कोई शिकायत नहीं की गई है।

वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया कि ऑटोनॉमस विवाद के विरोध के दौरान उन्हें हॉस्टल में बंद रखा गया और चेतावनी दी गई कि आवाज उठाने पर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। छात्राओं का कहना है कि डर और दबाव का ऐसा माहौल किसी भी शिक्षण संस्थान के मूल उद्देश्यों के विपरीत है। छात्राओं ने इसकी लिखित शिकायत एडीसीपी से की है।

बेटियों की शिक्षा के लिए मार्मिक पहल !

पांच सौ रुपए की कमी, टूटता सपना और फिर समाज का मिला संबल

बेटियों के मददगार प्रतिभा शर्मा अमरजीत सिंह डा. प्रशान्त सचान

»प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। एक छोटी सी रकमऱ सिर्फ पांच सौ रुपए। लेकिन इसी पांच सौ रुपए की कमी ने एक मासूम बेटी का स्कूल जाना रोक दिया। किताबें हाथ में लेने की उम्र में वह खेत में काम करने को मजबूर हो गई। उसकी आंखों में पढ़ने का सपना था, लेकिन हालात उससे भारी पड़ रहे थे। जब यह दृश्य विद्यालय के प्राचार्य की नजरों में आया, तो उन्होंने मानवता दिखाते हुए बेटी की फीस माफ कर दी। यह पल सिर्फ एक निर्णय नहीं था, बल्कि एक बेटी के भविष्य को बचाने की शुरुआत थी।

इस घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया, तो संवेदनशील दिलों को झकझोर गया। सवाल उठा कि क्या आज भी शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए बेटियों को संघर्ष करना पड़ेगा। इसी सवाल का जवाब बना एजूकेशन प्रोत्साहन समिति ढिंकची का अभियान 'एक कदम शिक्षा की ओर', जिसमें समाज के जागरूक लोगों ने आगे बढ़कर बेटियों का हाथ थाम लिया।

इस अभियान से जुड़ते हुए पुखरायां स्थित यशोदा मेडिकल सेंटर से जुड़े प्रशान्त सचान ने बेटी की शिक्षा के लिए बारह हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि बेटियों की पढ़ाई केवल परिवार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने में वे हमेशा साथ खड़े रहेंगे।

इसी क्रम में आर्यावर्त बैंक की सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी प्रतिभा शर्मा ने भी पांच हजार रुपए का सहयोग देकर यह साबित किया कि सेवा की भावना पद या उम्र की मोहताज नहीं होती। उनका कहना था कि अगर समय पर मदद मिल जाए, तो एक बेटी का भविष्य संवर सकता है और वही बेटी कल समाज को दिशा दे सकती है।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से बयोवृद्ध अमरजीत सिंह ने अपनी सीमित बचत से बारह सौ रुपए इकट्ठा कर बेटियों की शिक्षा के लिए दान दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनकी छोटी सी मदद से किसी बेटी की पढ़ाई जारी रह सके, तो इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं।

एजूकेशन प्रोत्साहन समिति से जुड़े दीपक भाई पटेल ने भावुक शब्दों में कहा कि बेटियां समाज की आधी आबादी नहीं, बल्कि पूरी उम्मीद हैं। अगर बेटियां पढ़ेंगी, तो परिवार सशक्त होगा, समाज बदलेगा और आने वाली पीढ़ी मजबूत बनेगी। इसलिए बेटियों की शिक्षा किसी दान की नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की मांग करती है।

यह कहानी सिर्फ आर्थिक सहयोग की नहीं है, यह उस संवेदना की कहानी है, जहां समाज ने एक बेटी के आंसुओं को पोंछा, उसके सपनों को सहारा दिया और यह भरोसा दिलाया कि पढ़ने की राह में वह अकेली नहीं है। यही सहयोग, यही संवेदना एक बेहतर समाज की नींव रखती है।

सीएम सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार पर ठेकदार को नोटिस जारी

» आयोजन की अव्यवस्थाओं पर जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, फर्म को नोटिस

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सीएम सामूहिक विवाह योजना के आयोजन को किसने पलीता लगाया इसकी जांच पूरी हो गई, रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी गई।

सामूहिक विवाह आयोजन में अव्यवस्थाओं के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा सभी संबंधित पहलुओं की विस्तृत जांच के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा भोजन व्यवस्था, लड्डू वितरण, जर्मन हैंगर के आकार, बैठने की व्यवस्था तथा विवाह आयोजन हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्री की गहन समीक्षा की गई, जिसमें कई व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं।

सीडीओ दीक्षा जैन ने बताया कि संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया जा रहा है। है। प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के पश्चात नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकरण में संबंधित फर्म को अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है। बीते रोज सीएसए ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। महीनों से चल रही तैयारी तब फेल हो गई जब टेंडर लिए फर्म ने पूरे आयोजन में घपला शुरू कर दिया। विभाग ने एक जोड़े पर खाने के लिए 15 हजार रुपए और गिफ्ट के लिए 24 हजार 500 रुपए का टेंडर दिया था। खाने से लेकर पानी पीने तक में सिर्फ अफरातफरी ही मचती रही। फजीहत के बाद प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच टीम बनाई।

स्वराज इंडिया
कानपुर सिटी
03

कानपुर में सामूहिक विवाह आयोजन में बड़ा घोटाला

खाने से लेकर लड्डुओं तक में भारी कटौती, जांच में खुली पोल

सीडीओ ने गठित की कमेटी

अव्यवस्था की आ रही शिकायतों पर सीडीओ दीक्षा जैन ने चार सदस्यी अफसरों की कमेटी गठित कर दी। सीडीओ ने बताया कि जांच समिति को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था एवं उपहार सामग्री वितरण करने वाली संस्था के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कार्य कराया गया है अथवा नहीं इसका गहनता से जांच कर रिपोर्ट जल्द दी जाए। कमेटी में एडीएम सिटी, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अधिशाषी अभियन्ता लोनिविए जिला समाज कल्याण अधिकारी का रखा।

टीम ने यह पाई कमी

- 15 हजार लोगों की जगह बना करीब चार हजार लोगों का खाना
- पानी पीने का ग्लास नहीं
- खाने के लिए रखी जाने वाली टेबल नहीं
- प्रत्येक जोडे को पांच किलो का लड्डू दिया जाना था, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को ही लड्डू की टोकरी दी गई
- तौल में लड्डू दो किलो के करीब मिली
- ड्राई फ्रूट की तौल में कमी
- विवाह पंडाल छोटा होने से तीन चरणों में विवाह हो सके
- हवन कुंड कम होने से परेशानी

अब अव्यवस्था का जिक्र

सामूहिक विवाह आयोजन के लिए जेम माध्यम से इसका कांट्रैक्ट हुआ था। पहले तो भोजन बनाने को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा। ष्ठरूसिटी, एडीएम आपूर्ति, एसीएम, डीएसओ, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय, तहसीलदार, बीएसए समेत कई अफसर खाने बनवाने में लग गए। पता चला इनके पास पर्याप्त हलवाई नहीं है। इसके बाद मची अफरतफरी खाने वाले हजारों की संख्या में और खाने बनाने वाले चंद, कैसे मैनेज होगा। अफसरों ने किसी प्रकार से पूरे पैनिक महौल को संभाला और भोजन बनवाने की व्यवस्था ठीक हो सकी।

पंडाल में खाने को टूट पडे लोग

खाना शुरू होते ही लोग टूट पडे, कोई पूडी खींच रहा तो कोई छोला प्लेट में भर ले रहा। जहां परोसने की व्यवस्था नहीं लोग झूठे हाथ से खाना निकाल ले रहे। अचानक बडी भीड को काबू करने को पुलिस बल बुलायी गई।

पांचवें दिन भी पूरे जोश के साथ डटे रहे अधिवक्ता

वकीलों ने उपमुख्यमंत्री, डीएम और एमएलसी को सौंपा ज्ञापन

» तहसील से दूर रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्ट किए जाने का मामला।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील परिसर से करीब दो-तीन किलोमीटर दूर रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बार एसोसिएशन एवं द लायर्स के अधिवक्ता पांचवें दिन भी पूरे जोश के साथ कलमबंद हड़ताल पर डटे रहे। अधिवक्ताओं ने इसे आम जनता और न्यायिक कार्यप्रणाली के लिए असुविधाजनक बताते हुए शासन से तत्काल निर्णय वापस लेने की मांग की।

बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेश कटियार एवं द लायर्स के अध्यक्ष प्रवीण कटियार नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कानपुर कचहरी पहुंचा। वहां कानपुर बार एसोसिएशन के सहयोग से जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय को तहसील से दूर गांव में शिफ्ट करने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ वादकारियों और आम नागरिकों को भी भारी परेशानी होगी। वहीं बिल्हौर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक अन्य पैनल ने बिल्हौर में जनता की शिकायतें सुन रहे विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) पाठक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और प्रस्तावित शिफ्टिंग के दुष्परिणामों से अवगत कराया। एमएलसी ने अधिवक्ताओं को उनकी मांग शासन स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व मंगलवार को अधिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री शीलू अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष रविनेश यादव, अमित मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से भेंट कर उपनिबंधक कार्यालय को तहसील से हटाकर गांव में शिफ्ट किए जाने की जानकारी दी थी और इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

रजिस्ट्री कार्यालय और ग्राम न्यायालय एक ही कैम्पस में होने चाहिए। अलग-अलग स्थानों पर होने से आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इस गंभीर विषय को लेकर मैंने जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी से वार्ता की है, ताकि जनहित में उचित निर्णय लिया जा सके।

– अरुण पाठक, एमएलसी

रजिस्ट्री कार्यालय को तहसील परिसर से हटाकर नई जगह स्थानांतरित किया जाना अधिवक्ताओं के साथ सरासर अन्याय है। यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनता को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि शीघ्र ही संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो अधिवक्ता समुदाय और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राज कुमार सिंह भदौरिया, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन बिल्हौर

अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। यह कलम बंद हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलता। जिलाधिकारी से वार्ता कर समस्या के बारे में अवगत कराया गया है।

– बृजेश कटियार,
अध्यक्ष, बिल्हौर बार एसोसिएशन

माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वार्ता कर प्रशासन से वार्ता करेंगे और समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो तथा जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न आए।

– उपेंद्र पासवान
जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण भाजपा

बार काउंसिल प्रत्याशी भी आंदोलन में उतरीं

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद की प्रत्याशी राधा यादव मंगलवार को बिल्हौर तहसील पहुंचीं। उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर रजिस्ट्री कार्यालय शिफ्टिंग के विरोध में आवाज बुलंद की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन को मजबूती प्रदान की।

राजस्व का नुकसान

अधिवक्ताओं की लगातार कलमबंद हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इससे शासन को प्रतिदिन भारी राजस्व की हानि हो रही है। अधिवक्ताओं के अनुसार रोजाना करीब 10 से 15 लाख रुपये तक के राजस्व नुकसान का अनुमान है। बावजूद इसके, अधिवक्ता अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने के मूड में नजर आ रहे हैं।

मकनपुर में बसंत मेले की तैयारियों का आगाज

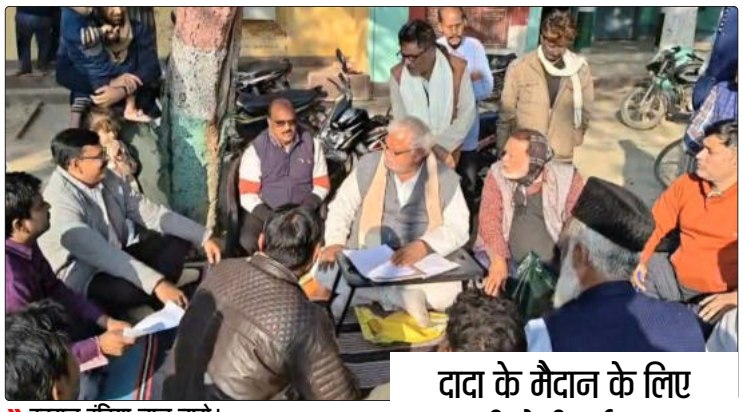

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (संवाददाता)। मकनपुर में बसंत पर्व पर आयोजित होने वाले सरकारी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत मंगलवार को मकनपुर पंचायत भवन में दादा के मैदान के लिए खुली बोली का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम बोली चार लाख उनसठ हजार रुपये रही। खुली बोली में नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत,स्थानीय लेखपाल सुनील चौधरी और ग्राम प्रधान मजाहिर हुसैन जाफरी उपस्थित रहे। बोली में कई लोग शामिल हुए, जिसमें सबसे अधिक बोली नियाजुद्दीन ने लगाई। ग्राम प्रधान ने बताया कि बसंत पर्व पर जिंदा शाह मदार की दरगाह के पर सरकारी मेला आयोजित किया जाता है। नियाजुद्दीन के पास दादा के मैदान का उपयोग सरकारी मेले के लिए करने का अधिकार रहेगा।

दादा के मैदान के लिए खुली बोली हुई संपन्न

कड़ाके की ठंड के बीच रात में तहसीलदार का औचक निरीक्षण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासनिक तैयारियों की जमीनी हकीकत जानने के लिए तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने बुधवार रात नगर क्षेत्र में अलाव प्वाइंटों और रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। बुधवार सुबह से ठंड में अचानक इजाफा होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है।

इस दौरान उन्होंने नगर पालिका चौराहा, बस स्टॉप सहित विभिन्न प्रमुख स्थलों पर स्थापित अलावों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने अलाव जलने की नियमितता, ईंधन की उपलब्धता और ठंड से राहत के असर को परखा। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। वहां ठहरने वाले जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध बिस्तर, कंबल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की स्थिति की समीक्षा की। तहसीलदार ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए कि रात के समय विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि ठंड से किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो। उन्होंने अलावों के नियमित संचालन और रैन बसेरों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।

मिशन शक्ति के तहत स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम

शिवराजपुर/बिल्हौर (कानपुर)। मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत थाना शिवराजपुर की एंटीरोमियो टीम ने नौरंगाबाद गांव स्थित स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

इस दौरान स्कूल की बच्चियों को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी दी गई। टीम द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1090, 1076, 1098, 112 व 181 के उपयोग के बारे में बताया गया।

स्वराज इंडिया

www.www.swarajindianews.com.com

वैचारिक मंच

कानपुर, बुधवार 17 दिसंबर , 2025

सम्पादकीय

बूथ-स्तरीय अधिकारियों पर तनाव का असर

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत-फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा-तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। निस्संदेह, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेर केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है।

उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं।

लाल किला विस्फोट से उठे कुछ सवाल और सबक

ज्योति मल्होत्रा

दिल्ली में लाल किला बम विस्फोट मामला दिल दहलाने वाला है। हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस के यत्नों से फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा पकड़ा गया जिससे भारी तबाही टल गयी। ऐसी घटनाएं टालने को हमें अपने पुलिस थानों के नेटवर्क को... दिल्ली में लाल किला बम विस्फोट मामला दिल दहलाने वाला है। हालांकि जम्मू-कश्मीर पुलिस के यत्नों से फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा पकड़ा गया जिससे भारी तबाही टल गयी। ऐसी घटनाएं टालने को हमें अपने पुलिस थानों के नेटवर्क को और मज़बूत करना होगा क्योंकि वे हमारे सुरक्षा तंत्र की मुख्य धुरी हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीतिक एकजुटता भी ज़रूरी है।

नई दिल्ली में हुए कार विस्फोट को कुछ अर्सा बीत चुका है। काफी वक्त बीत चुका और जांच ने रफ़्तार एवं दिशा पकड़ ली है। हमले संबंधी अलग-अलग थ्योरियों को समझाने और खुलासे करने के लिए इतना समय पर्याप्त है। लाल किले के गेट के पास हुआ विस्फोट दहलाने वाला और धृष्टता रोंगटे खड़े करने वाली थी।जो बात एकदम दिमाग में आती है वह यह है कि योजनाएं लंबे समय से बन रही होंगी; प्रोफेशनल्स (अधिकतर डॉक्टर) को इसे अंजाम देने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया, और इसमें काफी समय लगता है। (यह फिल्मों में दिखाए जाने वाले काम जितना आसान नहीं,बल्कि इसके लिए बहुत कौशल चाहिए)। टार्गेट चुने गए, रेकी की गई और एक साथ कई इलाकों में बड़े पैमाने के हमले करने के लिए इस जाल के सब धागों के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया। ऐसा लगता है कि इस बार हमारी पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह बेखबर थीं और एक बहुत खतरनाक दुश्मन संगठन के मंसूबों और गतिविधियों को पकड़ नहीं पाईं। यह सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की कारगुजारी रही, जिसने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा, जिससे आगे चलकर आतंकवादियों के एक जटिल और बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ और दिल्ली एवं अन्य जगहों पर तबाही मचाने की उनकी नापाक योजना का पता चल सका ।ऐसा लगता है कि ये आतंकवादी तुर्की और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे थे। गतिविधियों का केंद्र फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज लगता है, और कथित तौर पर इसका उद्गम स्थल कश्मीर है। कतिपय कारणों से, प्रशासन में बैठे लोग जम्मू-कश्मीर से स्थानीय आतंकवादियों का सफाया कर दिए जाने का दावा करते रहते हैं।। जाहिर है, पकड़े गए लोगों से पूछताछ ही इन हिरासतों और बरामदगी का आधार है। मुझे इस बात की चिंता है कि प्रथम विचार से लेकर लोगों को प्रशिक्षित करने तक, सामग्री खरीदना, टार्गेट चुनना और लोगों एवं सामान की तैनाती, यह एक मुश्किल और समय लेने वाला काम है, जिसे अत्यंत गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया। ज्यादातर काम पूरे हो चुके थे और आखिरी दांव चलने को था, लेकिन हम बहुत बड़ी तबाही देखने से बच गए... यह हमारी खुशनसीबी रही। हालांकि, यहां गौरतलब कि शुरुआती कामयाबी जम्मू-कश्मीर पुलिस के यत्नों से मिली, जिसने फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा ढूंढ़ निकाला। बढ़िया पुलिस कारगुजारी यही होती है।अगला स्वाभाविक प्रश्न जो साफ तौर पर उठता है वह यह कि - इस किस्म के कितने आतंकी समूह अभी भी सक्रिय हैं? उनकी संरचना और संभावित निशाने क्या हैं? इन कुकृत्यों के असली गुनहगार कौन हैं? उम्मीद है, ये प्रश्न हमारे देश के संबंधित अधिकारियों और संगठनों को चौबीसों घंटे काम करते रहने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प समझ में नहीं आता। आज, जब स्थितियां और भी ज्यादा नाजुक हैं।

भूख से मुकाबले के साथ जलती शिक्षा की लौ

गुणवत्ता बेहतर बनाए रखी

ज्वाला सिंह दास

अक्षय पात्र का भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने को 2000 में शुरू हुआ संकल्प आज चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर चुका है। जो सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को स्कूलों में भोजन करा रहा है। महाभारत की एक कथा के अनुसार जब वनवास के दौरान पांडव सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र देते हैं, जिसका भोजन कभी खत्म ही नहीं होता। इस्कॉन का अक्षय पात्र भी पांडवों के अक्षय पात्र की तरह हो गया है-भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने का आज यह बड़ा सहारा बन गया है।

साल 2000 में शुरू हुआ यह संकल्प आज चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर चुका है। अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को नियमित रूप से उनके स्कूलों में भोजन करा रहा है। साल 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि खाद्य निगम के गोदामों में काफी मात्रा में अन्न सड़ जाता है। उस अन्न के जरिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तर्क जंचा और उसके ही आदेश पर समूचे देश के स्कूलों में दोपहर में बना हुआ भोजन

देना जरूरी कर दिया गया। इसके पहले केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय पोषण योजना के तहत चुने हुए ब्लॉकों में शुरुआत की थी, जिसके तहत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराना शुरू हुआ। । अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का भी एक संकल्प कार्य कर रहा है। स्वामी प्रभुपाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी खिड़की से देखा, कूड़े में फेंके गए भोजन को लेकर कुत्ते और कुछ बच्चों में खींचतान चल रही थी। यह कारुणिक दृश्य देखकर प्रभुपाद परेशान हो गए। उन्होंने तब संकल्प लिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भूखा रहने को मजबूर न हो सके। इस्कॉन के मंदिरों में यह व्यवस्था अहर्निश अब तक जारी है।बहरहाल, दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की स्थापना 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। पहले साल इस योजना के तहत बेंगलुरू के पांच स्कूलों के 1,500 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तब से फाउंडेशन कार्य कर रहा है। अक्षय पात्र योजना का उद्देश्य कुपोषित बच्चों को भोजन मुहैया कराना और उन्हें शिक्षा हासिल करने में सहयोगी बनना है। कालांतर में संस्था का विस्तार तेजी से हुआ। अक्षय पात्र के जरिए अब तक चार अरब से ज्यादा थालियां खिलाई जा चुकी हैं। अक्षय पात्र की पहुंच आज 23,978 से अधिक स्कूलों तक हो गई है। इस साल मार्च में अक्षय पात्र ने अपना 78वां रसोईघर स्थापित किया। सहयोग पर भी निर्भर है। अक्षय पात्र ने न सिर्फ भोजन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखी है, बल्कि पौष्टिकता और पोषण का भी ध्यान रखा है। उसके पास जो 78 रसोईघर हैं, वे पूरी तरह मशीनीकृत हैं। उनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सैकड़ों लोगों द्वारा तैयार भोजन को स्कूलों और आंगनबाड़ियों को पूरी तरह एयर कंडिशंड व्यवस्था में भेजा जाता है।

कलेक्ट्रेट परिसर में एलआईयू टीम ने की सघन सुरक्षा जांच

» मेटल डिटेक्टर से हुई तलाशी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार को एसीपी एलआईयू के नेतृत्व में एलआईयू टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और पूरे परिसर में सघन जांच अभियान चलाया। टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभी कार्यालयों की तलाशी ली। परिसर में आने वाले लोगों के बैगों की जांच की गई, वहीं खड़े वाहनों को भी मेटल डिटेक्टर से चेक किया गया।

जांच के दौरान पार्क में लगी सीटों, पेड़ों के आसपास और वाहनों के नीचे तक टीम ने बारीकी से तलाशी ली। कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर एनआईसी कार्यालय सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों को चेक किया गया।

डीएम कार्यालय के बाहर खड़े लोगों से पूछताछ कर आने का उद्देश्य भी जाना गया।

अचानक हुई सुरक्षा जांच से कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट आने वाले लोगों में हल्की अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि एलआईयू टीम ने उन्हें बताया कि यह नियमित सुरक्षा जांच है।

एसीपी एलआईयू संजय राय ने बताया कि आगामी

त्योहारों और 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए यह रूटीन चेकिंग की जा रही है।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

ट्रेन के इंतज़ार में बैठी महिला का बैग चोरी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। लखनऊ से मेमू ट्रेन द्वारा कानपुर सेंट्रल पहुंची एक बुजुर्ग महिला का बैग अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। महिला दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। महिला के अनुसार बैग में करीब 2500 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, पिन कार्ड, पासपोर्ट समेत जरूरी दस्तावेज और दवाइयां रखी थीं। पीड़ित महिला राजदा पत्नी मुन्ना, निवासी काशीराम कॉलोनी, चिनहट, लखनऊ ने जीआरपी थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और बैग बरामद कराने की गुहार लगाई है। जीआरपी स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

आरपीएफ ने ओएचई तार चोरी करने वाले दो शातिरों को दबोचा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चंदारी-चकेरी स्टेशन के बीच ओएचई वायर काटकर चोरी करने दो शातिर चोरों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरपीएफ कानपुर सेंट्रल के निरीक्षक एस.एन. पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सुरागरसी के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

टीम ने 15 दिसंबर 2025 को किलोमीटर संख्या 1013/22ङ्क24 पर चंदारी से चकेरी के बीच रेलवे लाइन के उत्तर की ओर दोनों आरोपियों को चोरी किए गए ओएचई तारों के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने 9 दिसंबर को मिलिट्री साइडिंग क्षेत्र में पोल से ओएचई वायर काटकर चोरी करना स्वीकार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अर्जुन सिंह यादव उर्फ कैप्टन और सोनू यादव उर्फ मुनीम निवासी कानपुर नगर के रूप में हुई है।

महिलाओं से जुड़ी विभिन्न शिकायतें सामने आईं, तीन मामलों का मौके पर निस्तारण

राज्य महिला आयोग ने देहात में लगाया जनता दरबार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली, जब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी जिले में पहुंचीं और जनता दरबार लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनीं। इस दौरान महिलाओं से जुड़ी विभिन्न शिकायतें सामने आईं, जिन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई।

राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनता दरबार में कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले पारिवारिक विवादों से जुड़े थे, जिनमें बेटे द्वारा मां को न रखने, मामूली घरेलू विवाद और दहेज उत्पीड़न जैसी शिकायतें शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि महिलाओं से संबंधित हर शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण हो, ताकि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षा और सम्मान मिला है, जिसके चलते अब शिकायतों की संख्या में भी कमी आई है।

(भाजपा में 'नवीन' प्रयोग की इनसाइड स्टोरी)

नितिन नबीन के नाम पर कैसे राजी हुआ आरएसएस !

नितिन नबीन का संघ परिवार से पुराना और मजबूत जुड़ाव रहा है, उनके पिता बिहार भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं

» भाजपा का लगातार झुकाव हिंदी भाषी राज्यों की ओर बढ़ रहा है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। भाजपा ने संगठन स्तर पर बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेताओं की मौजूदगी रही। मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।

भाजपा ने बीते दो दिनों में संगठन को लेकर दो अहम फैसले किए हैं। एक ओर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो दूसरी ओर बिहार के नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।

दोनों ही निर्णय लंबे समय से प्रतीक्षित थे, लेकिन नितिन नबीन को राष्ट्रीय नेतृत्व में आगे लाया जाना सबसे अधिक चर्चा में है।

महज 45 वर्ष की आयु में नितिन नबीन भाजपा के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है।

वह बिहार से ऐसे पहले नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाया है। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है।सूत्रों के अनुसार, पिछले करीब डेढ़ वर्ष से भाजपा और संघ नेतृत्व के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में रहे, लेकिन अंततः नितिन नबीन के नाम पर सहमति बनी। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि आने वाले कुछ महीनों में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, नितिन नबीन का संघ परिवार से पुराना और मजबूत जुड़ाव रहा है।

उनके पिता बिहार भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और उनका परिवार दो पीढ़ियों से संगठन की विचारधारा के प्रति समर्पित रहा है। यही वजह रही कि जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, तो संघ की ओर से भी उस पर सहमति बनी। संघ की यह स्पष्ट राय थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध और नई पीढ़ी के नेता को मिलना चाहिए।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला अहम माना जा रहा है। बिहार से अध्यक्ष पद देकर भाजपा ने हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ और मजबूत करने का संकेत दिया है। मौजूदा समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य पार्टी के लिए सियासी पावर हाउस बने हुए हैं। ऐसे में इन राज्यों से नेतृत्व उभारना भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।पार्टी के भीतर नितिन नबीन की छवि एक साफ-सुथरे, विवादों से दूर और चुपचाप संगठनात्मक काम करने वाले नेता की रही है। उनकी सादगी और निरंतर मेहनत को ही इस बड़ी जिम्मेदारी का आधार बताया जा रहा है। भाजपा के इस 'नवीन' प्रयोग को आने वाले समय में संगठन और चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

590 ग्राम पंचायतों में 39 हजार डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया

ग्राम पंचायतों में 31 हजार नेट वोटर्स को जोड़ा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पंचायत चुनाव के 590 ग्राम पंचायतों में 39 हजार डूप्लीकेट वोटर्स को हटाया, वहीं करीब 31 हजार नए वोटर्स को जोडा गया है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सत्यापन के बाद इन वोटर्स का नाम सूची से हटा दिए गए हैं। अब 23 दिसंबर को सूची का अन्तिम प्रकाशन होगा। 24 से 30 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी जाएंगी जिसके संशोधन के बाद छह फरवरी को फाइनल सूची का प्रकाशन होगा। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पुनरीक्षण अभियान के बाद 23 दिसम्बर को अंतिम प्रकाशन होगा, फिर आपत्तियों ली जाएंगी।

पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कुल 590 पंचायतों में 247173 डूप्लीकेट वोटर्स (संभावित दोहराए गए मतदाता) की सूची थी।

अफसरों को सत्यापन के बाद कुल 190676 वैलिड वोटर्स मिले तो वहीं 39313 वोटर्स को नाम काटा गया है। 17184 वोटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयार की जा रही है। सबसे अधिक डूप्लीकेट वोटर्स कल्याणपुर ग्राम पंचायत के 11437 हटाए गए हैं।

अभियान में कुल 31,404 नेट वोटर्स जोडे गए हैं, इनमें अधिकांश पहली दफा वोट करने वाले शामिल हैं।

करीब दो प्रतिशत वोटर्स बढें हैं इनमें सबसे अधिक मतदाता ककवन और बिल्हौर में बढें हैं। वर्ष 2021 में जिले की 590 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में करीब 12.53 लाख मतदाता दर्ज थे। पांच वर्षों में हुए बदलाव, मृत्यु, पलायन और दोहरे नाम के चलते मतदाता सूची शुद्धिकरण की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ ने घर.घर जाकर मतदाताओं की पहचान की। सत्यापन के दौरान आधार के अंतिम चार अंक दर्ज करना अनिवार्य किया गया जो मतदाता दिए गए पते पर नहीं मिले या आधार विवरण उपलब्ध नहीं करा सकेए उन्हें डुप्लीकेट मानते हुए सूची से बाहर कर दिया गया।

वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले शुरू किए गए इस मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 1,78,151 नए मतदाता जोड़े गए। 24,546 मतदाताओं के नामों में संशोधन किया गया। 1,46,747 मतदाता हटाए गए ;(मृतक, स्थानांतरित या डुप्लीकेट)। इस प्रक्रिया के बाद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 12,84,460 हो गई है।

रूरा: खनन माफियाओं पर कार्रवाई से कांप रहे जिम्मेदारों के हाथ!

» खबर छपते ही ट्रैक्टर सीज, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं

» बड़ा सवाल,नहर पटरी से खनन करने वालों को कौन दे रहा संरक्षण ?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिगाई गांव में नहर पटरी में बालू खनन पर कार्रवाई अधूरी

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र में नहर पटरी से हो रहे अवैध बालू व मिट्टी खनन के मामले में प्रशासन ने एक ट्रैक्टर सीज कर कार्रवाई शुरू तो कर दी है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज न होना प्रशासनिक मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। स्वराज इंडिया में मामला उजागर होने के बाद हरकत में आए अफसरों की यह कार्रवाई फिलहाल अधूरी मानी जा रही है।

बताते चलें कि रूरा और तिगांई गांव के आसपास लंबे समय से नहर और रजबहों की पटरी को नुकसान पहुंचाकर अवैध खनन किया जा रहा था। इससे न केवल सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि किसानों के खेतों की मेड़ें भी कमजोर हो गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद न पुलिस ने कार्रवाई की और न ही सिंचाई विभाग ने गंभीरता दिखाई।

सूत्रों के मुताबिक नगर पंचायत रूरा के एक सभासद पर नहर पटरी से खनन कराने के आरोप हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच की बात कही जा रही है, लेकिन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होना संदेह पैदा कर रहा है।

सबसे बड़ा सवाल

जब अवैध खनन पकड़ा गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ और वाहन सीज किया गया, तो एफआईआर दर्ज करने में देरी किसके दबाव में हो रही है? अब निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। आखिर कौन माफियाओं को संरक्षण दे रहा है।

सिंचाई विभाग की लापरवाही उजागर

नहरों और रजवाहों से मिट्टी निकाले जाने के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। अब मामला सामने आने के बाद विभाग ने जेई को मौके पर भेजकर जांच शुरू की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभाग पहले सक्रिय होता तो नुकसान रोका जा सकता था।

रूरा पुलिस ने अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर को सीज किया है, लेकिन ना चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही खनन कराने वालों पर एफआईआर। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित है। किसानों की मांग ग्रामीणों और किसानों की मांग है कि अवैध खनन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए राजनीतिक व प्रशासनिक संरक्षण की भी जांच हो

किसान पाठशाला में पढ़ाया उन्नत कृषि का पाठ

» किसानों से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को किया साझा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। किसानों को खेती करने के आधुनिक तौर तरीके के साथ ही रासायनिक उर्वरकों की मात्रा का कितना प्रयोग करना चाहिए इसकी जानकारी दी गई। रसूलाबाद क्षेत्र में किसान पाठशाला के अंतर्गत पंचायत देवगांव उर्फ निभू के मजरा थानापुरवा में रवी फसल दलहन/तिलहन की नवीन प्रजातियों एवं उत्पादन तकनीकी के प्रभावी विंदु, प्राकृतिक खेती एव हरी खाद का महत्व बताया गया। साथ ही रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण एवं कृषि रक्षा, कृषि में ड्रोन का महत्व, फॉर्मर रजिस्ट्री का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। इफको प्रभारी अक्षय राज ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक को डालने विधि बताई। यहां प्रमुख रूप से कर्मचारी जगप्रसाद बीटीएम, अक्षय राज, पंचायत सहायक श्रीमती शांति देवी, प्रगतिशील कृषक कल्यान, नंदराम, जगरूप, योगेंद्र, नीरज देवी अन्य कृषक उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन की हुंकार अब शुरू करेंगे भूख हड़ताल

» 13वें दिन भी जारी रहा धरना-प्रदर्शन, रसूलाबाद, कहिंजरी के सचिव को बर्खास्त करने की मांग

» आरोप लगाया देर से शुरू की धान की तौल, व्यापारियों की तौल रहे धान, किसानों को टरका रहे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। साधन सहकारी समिति में देर से धान खरीद करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत गुट ने लगातार 13 वें दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार से किसान आमरण अनशन शुरू कर देंगे। किसानों के इस ऐलान से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए।

रसूलाबाद कस्बे में ब्लॉक परिसर में स्थित साधन सहकारी समिति में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह यादव ने बताया कि क्षेत्र के नैला, कटरा,सुजानपुर में हर घर जल योजना के तहत पानी की सप्लाई नहीं शुरू कई गई और न ही पाइपलाइन डाली गई। इसके अलावा क्षेत्र में संचालित पशु आश्रय स्थलों में व्यापक स्तर पर चारा,चोकर नहीं है। जिसके चलते बेजुबान पशु गौशालाओं में दम तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती को रोका जाए ताकि किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि धान खरीद केंद्रों में मनमानी की जा रही है। खासतौर से रसूलाबाद ब्लाक परिसर में स्थित धान खरीद केंद्र में देर से किसानों की खाद खरीदने का आरोप है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि व्यापारियों को प्राथमिकता जा रही दी जा रही है और किसानों को टरकाया जा रहा है। कहिंजरी स्थित साधन सहकारी समिति में भी यही आलम है। लगातार 13 वें दिन चल रहे धरना प्रदर्शन में कोई बड़ा अधिकारी किसानों से मिलने नहीं पहुंचा। वहीं किसानों ने बताया कि यदि उनकी जायज मांगों को नहीं माना जाता है तो वह शुक्रवार से धरना प्रदर्शन को भूख हड़ताल में तब्दील कर देंगे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

स्कॉर्पियो और कार की भिड़ंत में बच्ची समेत दो की मौत, माता-पिता गंभीर

गंभीर घायलों को भेजा गया हैलट अस्पताल, परिजनों में मचा कोहराम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुखरायां कस्बा स्थित रिलाइंस पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत में एक मासूम बालिका समेत दो की मौत हो गई। वहीं बच्ची के माता पिता बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक हलधरपुर गांव निवासी ग्राम प्रधान शमशुद्दीन ने बताया कि उनके भाई रिजवान अहमद 25 वर्ष मंगलवार को कानपुर से भोगनीपुर की तरफ आ रहे थे। वहीं बलिया निवासी परितोष व उनकी पत्नी शुवी अपनी पुत्री प्रिशा के साथ उरई से कानपुर जा रहे थे। तभी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास रिजवान की गाड़ी की दूसरी तरफ जाकर परितोष की गाड़ी से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में परितोष के 11 माह की पुत्री प्रिशा व रिजवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं परितोष और शुवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए पुखरायां सीएचसी

भेजा ।जहां मौजूद चिकित्सक ने प्रिशा व रिजवान को मृत घोषित कर दिया तथा परितोष और शुवी की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सडक़ हादसे में दो लोगों की मौत हुई है जबकि दो लोग घायल हुए हैं। घटना की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

पिकअप तेज चलाने के कॉम्पटीशन में चार गाड़िया टकराई

» दो लोग गंभीर घायल, हैलट में कराया गया

कानपुर देहात। थाना क्षेत्र के मधु निवादा मोड़ पर चार गाडियों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद सीएचसी से हैलट कानपुर रेफर किया गया। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलाबाद देहात ग्राम ग्राम पंचायत का मजरा रायपुर निवासी पूर्व प्रधान हरगोविंद सिंह अपनी भाभी कृष्णा देवी व बेटे शिवा के साथ कानपुर से वापस घर आ रहे थे। तभी मधुनिवादा मोड़ के पास रसूलाबाद की ओर से आ रहे दो पिकअप चालकों ने तेज चलाने का कॉम्पटीशन शुरू कर दिया। इस दौरान पिकअप चालकों ने उनकी कार और कानपुर की ओर से ही आ रहे लोडर में टक्कर मार दी । जिससे दो वाहन तो वहीं मौके पर पलट गए जबकि हरगोविंद सिंह की कार क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को आनंद-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद में भर्ती कराया गया। जहां शिवा और कृष्णा देवी को प्राथमिक उपचार करने के बाद वापस हैलट रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर लापरवाह पिकअप चालकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

बाइक और साइकिल की भिड़ंत में घायल की 108 एंबुलेंस ने बचाई जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

ब्यूरो कानपुर देहात। अकबरपुर थाना के अंतर्गत मुरीदपुर ओवरब्रिज के पास बाइक और साइकिल की आपसी टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान आशीष कुमार (उम्र 30 वर्ष) पुत्र राम प्रताप, निवासी ग्राम कुर्वा खुर्द, ब्लॉक सरवन खेड़ा के रूप में हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सेवा तत्काल मौके पर पहुंची। एंबुलेंस पर तैनात ईएमटी जसवंत सिंह ने घायल को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया। वहीं पायलट अटल बिहारी ने मरीज को शीघ्र अस्पताल पहुंचाया। अकबरपुर में प्राथमिक इलाज के बाद मरीज की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद राजस्थान के दो शातिर गिरफ्तार

शिवली पुलिस को मिली सफलता, दो तमंचे, कई कारतूस, दो मोबाइल फोन और बाइक बरामद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 16 और 17 दिसंबर की दरमियान रात में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शातिर गौतस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी राजस्थान के कोटा जिले के रहने वाले हैं और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है।

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पांडेय के निर्देश पर शिवली पुलिस टीम बैरी मैथा रोड पर हृदयपुर मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने एक बाइक पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने लगे। जिससे वे अनियंत्रित होकर गिर गए।

खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वे घायल हो गए। पुलिस की पूछताछ में घायलों ने अपना नाम मोहर सिंह और राजू बताया है। दोनों आरोपी राजस्थान के कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र स्थित टीन टपरिया के निवासी हैं। पुलिस

ने इनके पास से दो तमंचे, कई कारतूस, दो मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। इन बदमाशों ने बीती 11 दिसंबर को शिवली क्षेत्र में हुई एक गौतस्करी की घटना भी कबूल की है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि पकड़े गए दोनों अपराधी अंतरराज्यीय स्तर पर अपराध करते हैं। इनके खिलाफ कानपुर देहात, कानपुर नगर और हरदोई समेत विभिन्न जनपदों में आधा दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

इनमें गैंगस्टर एक्ट, गौवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता और पुलिस पर जानलेवा हमले जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

रास्ता पूछने का बहाना बना रची हत्या की साजिश

एसपी ग्रामीण की प्रेस वार्ता में खुलासा, जमीन की रंजिश में लोहे की रॉड से जानलेवा हमला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

अयोध्या। अयोध्या के ग्रामीण इलाके में अपराध का एक ऐसा चेहरा सामने आया है, जहां रास्ता पूछने की साजिश के पीछे हत्या की नीयत छिपी थी। थाना तारुन क्षेत्र के सोनौरा गऊपुर गांव में हुए इस सनसनीखेज हमले का खुलासा एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी की प्रेस वार्ता में हुआ है। पुलिस ने इस मामले में साजिशकर्ता सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है।

घटना 8 दिसंबर की रात की है। अंधेरे का फायदा उठाकर 7 से 8 आरोपी मोटरसाइकिलों से सोनौरा गऊपुर पहुंचे।

आरोपियों ने पहले रास्ता पूछने के बहाने शिवकुमार वर्मा को रोका और फिर अचानक लोहे की रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में शिवकुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों की मंशा साफ थी जान से मार देना।

एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि जमीन से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते पूरी योजना बनाकर कराया गया था। इसमें एक व्यक्ति ने साजिश रची और बाकी आरोपियों ने उसे अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, हमलावर पहले से हथियारों से लैस थे और घटना को अंधेरे में अंजाम देने के लिए समय और स्थान पहले ही तय किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना तारुन, हैदरगंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिससे एक-एक कर सभी आरोपियों की पहचान हो गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जिसने हमले की साजिश रची थी।

हाईकोर्ट बेंच की मांग पर: मेरठ बंद

बाजार सूने-दुकानों पर लटके ताल विभिन्न जिलों से मिला समर्थन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ में ऐतिहासिक बंद का असर सुबह से ही दिखाई दिया। बाजार बंद रहे, चिकित्सकों की ओपीडी स्थगित रही, जबकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गईं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर बुधवार को मेरठ में ऐतिहासिक बंद का ऐलान किया गया। सुबह से ही शहर के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। खैरनगर, बुढ़ाना गेट, बेगमपुल, दिल्ली रोड, गढ़ रोड और बच्चा पार्क समेत कई इलाकों में दुकानों के शटर नहीं खुले। वहीं कचहरी के गेट पर वकील सुबह से ही धरने पर बैठ गए। मेरठ बंद को शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 22 जिलों से समर्थन मिला है। मेरठ में सपा नेता अतुल प्रधान ने बंद को समर्थन दिया और व्यपारियों के बीच पहुंचे।मेरठ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी बंद को पूर्ण समर्थन दिया। आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी और सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने बताया कि बुधवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चिकित्सक ओपीडी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि, मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह बहाल रखी गईं।

बंद को सफल बनाने के लिए जिला बार एसोसिएशन और मेरठ बार एसोसिएशन की टीम सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच कचहरी से शहर के विभिन्न इलाकों में निकली।मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा, महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा, जिला बार अध्यक्ष राजीव त्यागी और महामंत्री अमित कुमार राणा ने अधिवक्ताओं के साथ जनसंपर्क किया।करीब 40 से अधिक टीमों ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर व्यापारियों और आमजन से बंद का समर्थन करने की अपील की। इस दौरान आनंद कश्यप, रविंद्र कुमार, देवकीनंदन शर्मा, पूर्व महामंत्री आशीष चौरसिया, सचिन त्यागी समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

सुबह 9:30 बजे तक खैरनगर, सुमित बुढ़ाना गेट, जिमखाना मैदान समेत कई इलाकों में दुकानों के शटरों पर ताले लटके रहे। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में आवाजाही कम दिखाई दी और बाजारों की रौनक पूरी तरह फीकी नजर आई।

तबादला एक्सप्रेस ने तोड़ा बाबुओं का वर्षों पुराना गठजोड़

नगर निगम में ढहा कुर्सियों का किला

» नगर आयुक्त ने वर्षों से एक ही कुर्सी पर जमे जेई, एई व बाबुओं का किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। नगर निगम अयोध्या में वर्षों से एक ही पटल पर जमे कर्मचारियों की जो अदृश्य सत्ता कायम थी, उस पर नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने एक झटके में करारा प्रहार कर दिया। यह सिर्फ स्थानांतरण नहीं, बल्कि सिस्टम की सफाई का साहसिक अभियान माना जा रहा है। नगर निगम के लगभग हर अनुभाग में ऐसी हलचल मची कि वर्षों से जमे चेहरे अचानक अपनी कुर्सियों से उखड़ते नजर आए।

निर्माण अनुभाग में लंबे समय से वार्डों में जमे

चार अवर अभियंता और चार सहायक अभियंताओं का कार्यक्षेत्र बदला गया। इसके साथ ही पेंशन अनुभाग से वरिष्ठ लिपिक अजय कुमार यादव, नगर आयुक्त कार्यालय के स्टेनो इंद्रसेन और वरिष्ठ लिपिक रंजीत कुमार को स्वास्थ्य अनुभाग भेजा गया।

लेखा अनुभाग से लिपिक कशिश को कर अनुभाग, कर से लिपिक अनुराधा गुप्ता और निहारिका को लेखा, जबकि कर अनुभाग से नैन्सी को निर्माण अनुभाग में स्थानांतरित किया गया। रिकॉर्ड से लिपिक तौहीद को रिकार्ड से कर चंद्रभान को कर अनुभाग भेजा गया।

मयंक तिवारी को डिस्पैच से निर्माण, जय श्रीवास्तव को विविध कर से भविष्य निधि, रमेश कुमार को कार्यशाला से कर तथा मनोज पांडेय को जन्म-मृत्यु पंजीकरण पटल से डिस्पैच अनुभाग भेजा गया। इसी क्रम में वरिष्ठ लिपिक राजेश यादव को भविष्य निधि से निर्माण, उद्यान एवं गोशाला, राजेश शंकर पांडेय को स्वास्थ्य विभाग से कार्यशाला, अवधेश त्रिपाठी को कर से रिकॉर्ड, गोविंदराज को रिकॉर्ड से स्टेनो नगर आयुक्त, मनोज गुप्त को रिकॉर्ड से कर, राजेश कुमार वर्मा को स्वास्थ्य से स्टेनो अपर नगर आयुक्त तथा राकेश तिवारी को निर्माण से स्वास्थ्य विभाग स्थानांतरित किया गया।

इतना ही नहीं, वर्षों से एक ही अनुभाग में तैनात आउटसोर्सिंग पर नियुक्त 42 कंप्यूटर ऑपरेटरों का भी पटल परिवर्तन कर दिया गया। नगर निगम के भीतर इस कार्रवाई को जयेंद्र कुमार का अब तक का सबसे सख्त और साफ संदेश माना जा रहा है नगर निगम किसी की निजी जागीर नहीं,

अब हर कुर्सी जवाबदेह होगी। नगर की जनता मानती है कि यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि वर्षों से जमी बाबूगिरी पर भी स्थायी ब्रेक लगाएगा।

रामनगरी में 19 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन

» राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगा मंथन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या 19 दिसंबर को वैश्विक वैश्य समाज की महत्वपूर्ण बैठक की साक्षी बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यसमिति का आयोजन मानस भवन में किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश से वैश्य समाज के प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेंगे। अधिवेशन के दौरान समाज सेवा, व्यापार, साहित्य और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा।

सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि बैठक में नेपाल, हांगकांग, थाईलैंड, दुबई, कनाडा और रूस सहित कई देशों व राज्यों से प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रामदास अग्रवाल की स्मृति में दिए जाने वाले रामदास अग्रवाल जनसेवा सम्मान सहित विभिन्न श्रेणियों में सम्मान प्रदान किए जाएंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

अमल गुप्ता बने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के क्षेत्रीय अध्यक्ष

अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष व लखनऊ उत्तर विधायक डॉ. नीरज बोरा ने अमल गुप्ता को अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने इस पर हर्ष जताया है। अमल गुप्ता ने नेतृत्व का आभार जताते हुए समाज को एकजुट करने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया है।

जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लग रही खून की बोली

» एनीमिया से पीड़ित किशोरी को एक यूनिट खून सात हजार रुपये में बेचा गया।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इलाज नहीं, दलाली!

अयोध्या। जिला अस्पताल जहां मरीज जिंदगी की आस लेकर पहुंचते हैं वहीं उसी छत के नीचे खून का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। ब्लड बैंक में सख्ती और जांच के तमाम दावों के बावजूद खून के सौदागर सक्रिय हैं और मरीजों की मजबूरी को अपना हथियार बना रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां एनीमिया से पीड़ित एक किशोरी को एक यूनिट खून सात हजार रुपये में बेचा गया।मेडिकल वार्ड के बेड नंबर 39 पर भर्ती सगुन सिंह, निवासी ग्राम अमावा सूफी, थाना खंडासा, का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉ. प्रशांत द्विवेदी ने खून की कमी बताते हुए रक्त चढ़ाने की सलाह दी। परिजन ब्लड बैंक पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें मदद के बजाय एक दलाल मिला। आरोप है कि रामनगर निवासी महेश ने सात हजार रुपये ऑनलाइन भुगतान लेकर खून की व्यवस्था करा दी। खून खरीदे जाने की पुष्टि खुद मरीज और परिजनों ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश सिंह के सामने की है।

सीएमएस के अनुसार, परिजनों ने ऑनलाइन भुगतान की बात स्वीकार की है, लेकिन लिखित शिकायत न मिलने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। यही वह खामोशी है, जिसमें सौदागर पनपते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस रैकेट में जिला अस्पताल का एक पूर्व सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है, जो ब्लड बैंक कर्मियों से पुरानी पहचान के दम पर खून का सौदा कराता है। लोगों का सवाल है कि क्या अस्पताल प्रशासन शिकायत का इंतजार करता रहेगा, या खून के इस काले कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी?

78वें पीएसी स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी

साहस, अनुशासन, कठिन प्रशिक्षण व कर्तव्यनिष्ठा ही जवानों की पहचान

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि 78 वर्षों से पीएसी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग व समर्पण का रहा है। सीएम योगी ने जवानों से अपील की कि साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, व्यावसायिक दक्षता व कठिन प्रशिक्षण ही आपकी पहचान बननी चाहिए। सरकार आश्वस्त करती है कि आपके सम्मान व सरकार के स्तर पर मिलने वाली सुविधा-संसाधन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मविश्वास का प्रमुख कारण कानून का राज है। कानून का राज सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही सुशासन की गारंटी दे सकता है। सुशासन में ही निवेश सुरक्षित हो सकता है और सुरक्षित निवेश ही युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री ने यूपीपीएसी के स्थापना दिवस समारोह-25 का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने पीएसी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया। सीएम ने 78वर्ष के गौरवशाली इतिहास के लिए पीएसी बल को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पीएसी बल आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, प्रदेश में महत्वपूर्ण त्योहारों, अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन, लोकतंत्र के महापर्व %चुनाव% को शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने के साथ ही संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य करता है। पीएसी के अधिकारी व कार्मिक विभिन्न आयामों के माध्यम से न सिर्फ यूपी, बल्कि देश के अंदर यूपी पीएसी बल, एसएसएफ, यातायात पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक ड्यूटी, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक, एटीएस व एसटीएफ कमांडो के रूप में सेवाएं प्रदान कर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

उन्होने पीएसी बल के अदम्य साहस की चर्चा करते हुये बताया कि 30वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले का जवाब दिया और पांचों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या में आतंकी हमले के दौरान सीआरपीएफ, पीएसी और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी आतंकियों को मार गिराया गया था।

उन्होने कहा कि पीएसी कार्मिकों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए पूर्व में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को अपडेट करते हुए एबीसी आदि ग्रेड सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पीएसी में 41,893 आरक्षियों व 698 प्लाटून कमांडर की भर्ती की। सीधी भर्ती के अंतर्गत प्लाटून कमांडर के पद पर 1648 तथा आरक्षी के पद पर 15131 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। इसमें 135 प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही यह भर्ती भी संपन्न होगी। सेवा के दौरान दिवंगत जवानों के 396 आश्रितों को आरक्षी व 58 आश्रितों को प्लाटून कमांडर के पद पर सेवायोजन प्रदान किया गया। आरक्षी पद हेतु 28 अभ्यर्थियों व प्लाटून कमांडर पर 7 अभ्यर्थियों के सेवायोजन की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। पीएसी में पदोन्नति के और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सशस्त्र पुलिस में 184 निरीक्षकों, 3772 उपनिरीक्षकों के पदों में वृद्धि की गई है।

विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 426 उप निरीक्षक, 4042 मुख्य आरक्षी तथा 13313 आरक्षियों को पदोन्नति दी गई। 352 मुख्य आरक्षी, 1015 आरक्षियों की पदोन्नति कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। योगी ने कहा कि पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल संचालित हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ केस की सुनवाई अब लखनऊ की कोर्ट में होगी, मिली मंजूरी

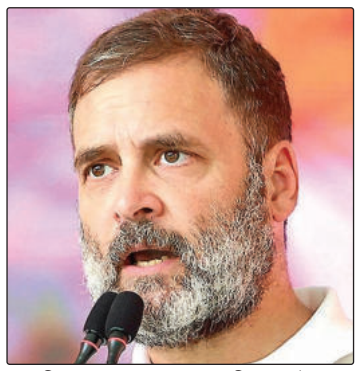

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। लखनऊ राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में चल रहे एक मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में होगी। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने याची की स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

दरअसल, भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। उसके द्वारा दाखिल अपराधिक परिवाद पर सुनवाई रायबरेली की विशेष कोर्ट में चल रही है। इस पर शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके आग्रह किया था कि यह केस लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्हें रायबरेली में उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। वादी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से ,रायबरेली की अदालत में चल रहे परिवाद को लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की गुहार की थी।

हर तीन साल पर किताब बदलकर लाखों का कमीशन खा रहा मिशनरी स्कूल

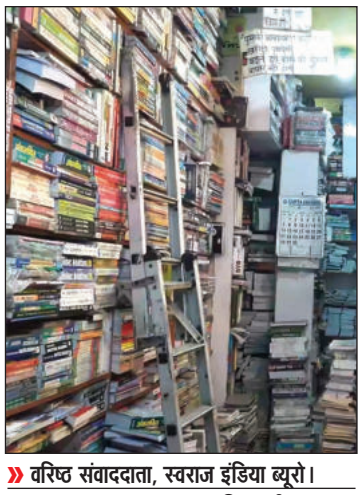

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। लखनऊ का एक मिशनरी स्कूल हर 3 साल पर किताबें बदल देता है। कमीशन खोरी के चक्कर में अभिभावकों को जमकर चूना लगाया जाता है। मामले की पुलिस से शिकायत हुई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्कूल अपने खाते में बुक सेलर से कमीशन जमा करवाता है।

» मामले की पुलिस से शिकायत, बुक्सेलर से खाते में कमीशन मांगने का आरोप।

लखनऊ निवासी आफताब आलम ने पुलिस उपायुक्त मध्य जोन को शिकायती पत्र दिया है। दिए शिकायती पत्र में आरोप है कि क्रिश्चियन विशप कैथोलिक डिवसेस संस्था कार्यालय स्थित हजरतगंज थाना हजरतगंज लखनऊ द्वारा हर 3 वर्ष पर उत्तर प्रदेश के मिशनरी स्कूल को सर्कुलर जारी कर अभिभावको को उनके अनुसार नई किताबें खरीदने के लिए आदेशित किया जाता है।

उक्त किताबों की कीमत अत्याधिक नियत कराकर बुक पब्लिशर से भारी रकम कमीशन के रूप में वसूल की जाती है।, उल्लेखनीय हो कि डिवसेस संस्था CARITS के नाम से उसका बैंक खाता 0363101560393 केनरा बैंक हजरतगंज लखनऊ में है। जिसमें उक्त कमीशन की अवैध रकम को विभिन्न पब्लिशर द्वारा खाते में भेजी जाती है। जिसके समस्त प्रमाण प्रार्थी के पास है। डिवेसस के उक्त कृत्य से अभिभावको को काफी अधिक मूल्य की पुस्तके खरीदने के लिए बाध्य होना पडता है तथा उनकी मेहनत से अर्जित की रकम को उपरोक्त संस्था द्वारा छल व धोखाधडी से अपने अनैतिक कृत्यों व धार्मिक कन्वर्जन इत्यादि में खर्च किया जाता है। जिसका विपरीत प्रभाव समाज पर पड़ रहा है।

जो कि गंभीर जांच का विषय है। शिकायतकर्ता ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराकर कार्यवाही करने व समस्त दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन ने पाचंवी बार विजय प्रकाश को चुना अध्यक्ष

जौनपुर में पत्रकार एकजुटता की मिसाल, सर्वसम्मति से हुआ अध्यक्ष का चयन

» वरिष्ठ संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

जौनपुर। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन की जौनपुर ईकाई की वार्षिक बैठक बीते रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जौनपुर पत्रकार भवन में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की मजबूती, कार्यों की समीक्षा और आगामी रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें बीते दिनों में यूनियन द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्यों ने यूनियन की गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य के लिए नई दिशाएं तय की।

आगामी वर्ष 2026 के लिए नए सदस्यों को जोड़ने के लिए एक व्यापक और प्रभावी सदस्यता अभियान चलाने की योजना पर सहमति बनी।

इस सर्वसम्मत निर्णय पर उपस्थित सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया और विश्वास जताया कि श्री मिश्र के नेतृत्व में यूनियन पत्रकार हितों के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। विजय प्रकाश मिश्र ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और पत्रकारों के हक की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक की अध्यक्षता विजय प्रकाश मिश्र और संचालन महामन्त्री सन्तोष कुमार सोन्थालिया ने किया।

बैठक के अन्त में वरिष्ठ पत्रकार सरदार जोगेन्दर सिंह के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शान्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई।इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष आदर्श कुमार, दीपक चिटकारिया, यशवन्त कुमार गुप्त कोषाध्यक्ष, डा.आशाराम, अरुण कुमार सिंह, प्रमोद कुमार पाण्डेय, चन्द्र मणि पाण्डेय, डा. प्रमोद कुमार सैनी, चन्द्र प्रकाश तिवारी, सतीश चन्द्र शुक्ल सतपथी, शिव कुमार गुप्त, बिहारी लाल यादव, संजय कुमार शुक्ल, विनोद कुमार यादव, राजेश कुमार गुप्त, अमरेश कुमार पाण्डेय, विनोद कुमार यादव, जनार्दन मिश्र, मोहर्रम अली, प्रेम प्रकाश मिश्र, आलोक सिंह, दीपक कुमार मिश्र, सुधाकर शुक्ल, बृजेश कुमार मिश्र, रविकांत, सचिन श्रीवास्तव, नीरज यादव, ऋतिक अरोड़ा, वीरेंद्र पाण्डेय, जुबेर अहमद,अमित कुमार मिश्र, आरिफ अंसारी, अजीत सिंह, विकास शुक्ल, उमेश यादव, आनंद मिश्र, ओमप्रकाश दूबे, संजय उपाध्याय आदि पत्रकार उपस्थित रहे।